

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1-4 अपील संख्या 221 से 224 / 2009 / जयपुर

मैसर्स किसान मोल्डिंग्स,
0-14, तृतीय मंजिल, अम्बर टॉवर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
बनाम

.....अपीलार्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवचन, जोन प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित:

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05 / 4 / 2017

निर्णय

1. उपर्युक्त चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 28.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 61 व 55 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

| अ.सं. | अ.अ. की अपील सं. | कर निर्धा. आ. दि. | कर निर्धा. तिमाही | अन्तर कर | ब्याज | शास्ति | कुल राशि |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|----------|----------|
| 221/09 | 101/2007-08 | 31.10.07 | प्रथम तिमाही | 80,958 | 3,643 | 1,61,016 | 2,46,517 |
| 222/09 | 102/2006-07 | 31.10.07 | द्वितीय तिमाही | 98,890 | 13,350 | 1,97,780 | 3,10,020 |
| 223/09 | 103/2006-07 | 31.10.07 | प्रथम तिमाही | 71,062 | 11,874 | 1,43,024 | 2,27,760 |
| 224/09 | 104/2006-07 | 31.10.07 | चतुर्थ तिमाही | 60,584 | 4,544 | 1,21,168 | 1,86,296 |

2. चारों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.09.2007 को अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा SWR Pipe & Fitting फिलेश टैंक, शीट कवर, पी.वी. सी. साल्वेन्ट सीमेंट, रबर ल्यूब्रिकेन्ट का हैड ऑफिस से स्टॉक ट्रांसफर के रूप में प्राप्त कर राजस्थान में कर वसूल कर जमा करवाना बताया। अपीलार्थी द्वारा SWR Pipe & Fitting पी. वी.सी. साल्वेन्ट पर 4 प्रतिशत की कर दर से वैट वसूल किया जाकर जमा करवाया गया तथा फिलेश टैंक, शीट कवर, रबर ल्यूब्रिकेन्ट पर 12.5 प्रतिशत की कर दर से वैट वसूल कर जमा करवाया गया। अपीलार्थी को वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के वस्तुवार विक्रय विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में विवरण प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत विवरणों के आधार पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा साल्वेन्ट सीमेंट का आलौच्य अवधि में विक्रय 4 प्रतिशत की कर दर से वैट वसूल किया गया है। उक्त बिक्रित वस्तु साल्वेन्ट सीमेंट शिडयूल की क्रम संख्या I to IV में कहीं भी उल्लेखित नहीं है अर्थात् इस पर शिडयूल V की कर दर प्रभावी होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने आलौच्य अवधियों में साल्वेन्ट सीमेंट के विक्रय पर धारा 25 के अधीन 8.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित अन्तर कर, धारा 61 के तहत शास्ति एवं धारा 55 के तहत ब्याज आरोपित किये गये। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत सोल्वेन्ट सीमेंट कोई सीमेंट गम अधेसिव नहीं है। वास्तव में यह पी.वी.सी. रेजिन का ही एक तरल रूप है तथा फिटिंग्स का ही एक रूप है। बिक्रीत सोल्वेन्ट सीमेंट (PVC RESIN) केवल पाईप फीटिंग के रूप में ही आता है। इसके बाद यह पाईप में ही बदल जाता है अर्थात् (MELT) हो जाता है जबकि अधेसिव आदि का अस्तित्व रहता है, वे केवल जोड़ने के काम आते हैं। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए, प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को उचित बतलाया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

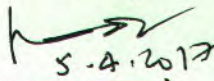
6. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस, लिखित बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा सोल्वेन्ट सीमेंट की राज्य में स्टॉक ट्रॉसफर के माध्यम से प्राप्ति की जाकर राजस्थान राज्य में विक्रय किया जाता है एवं व्यवहारी द्वारा "सोल्वेन्ट सीमेंट" पर 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्व घोषित किया गया है, व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु 'सॉल्वेन्ट सीमेंट' वैट एक्ट में प्रदत्त शिड्यूल की क्रम संख्या I to IV में कहीं भी उल्लेखित नहीं है अर्थात् इस पर शिड्यूल V के अनुसार सामान्य कर दर प्रभावी होती है।


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वा.क.अ. बनाम रस्तोगी स्टील फर्नीचर (2003) Tax Update Vol. 6 Part 8 Page 317) के मामले में विधिक स्थिति पर विस्तृत विचार कर निर्णित किया है कि कर निर्धारण आदेश में गणना किये गये कर पर ब्याज की देयता कर देयता की तिथि से ही प्रभावी होगी, जिसका संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है-

"As none of the cases cited at bar deals with like provision as are in consideration, they are of little assistance except the decision in J.K. Synthetics (Supra) as discussed above which throws sufficient light on the changes that have been brought about by substitution of s. 11-B with effect from 07-04-1979 vis a vis provision which was in force during the period for which dispute was before the Court. It clearly pointed out the shift in the basis of levy of interest from failure to pay tax due as per assessee under s.7(2) and (2-A) to non-payment of tax due as per assessment. It gave effect to principle of ex hypothesi determination of tax on occurrence of taxing event."

7. उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 4271 से 4274/2005/जयपुर सीटीओ बनाम रिलायंस इण्डस्ट्रीज निर्णय दिनांक 26.07.2007 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 के आलौच्य में शास्ति आकर्षित नहीं होती है, अतः शास्तियों के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


5.4.2017
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष